Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 02 नवंबर, 2020

drishtiias.com/hindi/printpdf/rapid-fire-current-affairs-02-november-2020

इंदिरा गांधी

31 अक्तूबर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु की पुत्री इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर, 1917 को प्रयागराज (इलाहाबाद) में हुआ था। इंदिरा गांधी एकमात्र महिला हैं, जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। ध्यातव्य है कि इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल के बाद सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली देश की दूसरी प्रधानमंत्री थीं। वर्ष 1959 में उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और वर्ष 1964 में प्रधानमंत्री नेहरु की मृत्यु के बाद उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्त्व में एक कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया, किंतु लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु के बाद वर्ष 1966 में वे देश की 5वीं प्रधानमंत्री बनीं। वर्ष 1975 में उनके कार्यकाल के दौरान भारत में आपातकाल लागू किया गया, जो कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक 'काला अध्याय' माना जाता है। आपातकाल की समाप्ति के बाद हुए चुनावों में वे हार गईं, जिसके बाद वर्ष 1980 में हुए चुनावों में एक बार फिर सत्ता में आईं। प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी के दूसरे कार्यकाल के दौरान अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' को अंजाम दिया गया। 31 अक्तूबर, 1984 को उनके दो सिख अंगरक्षकों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी को उनके मज़बूत व्यक्तित्त्व के लिये जाना जाता था और उन्होंने बांग्लादेश के गठन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो

आयुष मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया (Invest India) आयुष क्षेत्र की योजनाबद्ध और व्यवस्थित विकास को सुविधाजनक बनाने के लिये 'रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो' (SPFB) नामक एक रणनीतिक नीति इकाई स्थापित करने के लिये सहयोग करेंगे। 'रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो' (SPFB) की स्थापना एक अग्रगामी कदम है जो कि आयुष प्रणालियों (Ayush Systems) को भविष्य के लिये तैयार करेगा। यह ब्यूरो रणनीतिक और नीतिगत पहल करने में आयुष मंत्रालय की सहायता करेगा और इस क्षेत्र की पूर्ण क्षमता तक पहुँचने तथा इसमें विकास और निवेश को प्रोत्साहित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। ऐसे समय में जब कोरोना वायरस महामारी विश्व भर के तमाम लोगों को प्रभावित कर रही है और लोग अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं, तो इस तरह की रणनीतिक इकाई आयुष क्षेत्र के हितधारकों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण हो सकती है। इस परियोजना में एक भागीदार के रूप में इन्वेस्ट इंडिया, आयुष मंत्रालय के साथ बड़े पैमाने पर सहयोग करेगा ताकि ब्यूरो की कार्य योजना तैयार की जा सके और इसके अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्षयों को परिभाषित किया जा सके। साथ ही इन्वेस्ट इंडिया, ब्यूरो की कार्य योजना को लागू करने और कार्यान्वित करने के लिये प्रशिक्षित और विशेषज्ञ लोगों की भी नियुक्ति करेगा।

राजस्थान में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध

राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न हुए खतरे के मद्देनज़र राज्य में त्योहार के सीज़न के दौरान पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने कहा कि 'इस चुनौतीपूर्ण समय में राज्य सरकार के लिये लोगों की जीवन रक्षा करना और उन्हें वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचाना सर्वोपरि है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों और आम जनता को ज़हरीली हवा से बचाने के लिये राजस्थान सरकार ने राज्य में पटाखों की बिक्री करने वाले लोगों और प्रदूषण से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कई अध्ययनों में यह सामने आया है कि वायु प्रदूषण के कारण कोरोना संक्रमण और उसके कारण होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि राजस्थान सरकार के इस निर्णय का अनुसरण करते हुए देश के अन्य राज्य भी अपने क्षेत्राधिकार में प्रदूषण के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे।

एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

वर्ष 2005 में हुए एक उपग्रह सौदे को रद्द करने के लिये एक अमेरिका की एक अदालत ने इसरो (ISRO) की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बंगलुरू स्थित स्टार्टअप, **देवास मल्टीमीडिया** को 1.2 बिलियन डॉलर का मुआवजा देने को कहा है। वर्ष 2005 में एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दो उपग्रहों के निर्माण, लॉन्च और संचालन के लिये देवास मल्टीमीडिया के साथ समझौता किया था, जिसे वर्ष 2011 में एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन द्वारा रद्द कर दिया गया। बंगलुरू स्थित एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्यरत भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी है, जिसे सितंबर 1992 में अंतरिक्ष उत्पादों, तकनीकी परामर्श सेवाओं और इसरो द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिक दोहन व प्रचार प्रसार के लिये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था।